रिपोर्टयोग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय न्यायपालिका

आपराधिक आवेदन संख्या (एस).1378-1379 ऑफ 2023

उग्रसेन **.....अपीलकर्ता(गण)**

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य **.....प्रतिवादी(गण)**

निर्णय

एस. रवींद्र भट्ट, जे.

1. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय[2] द्वारा पारित निर्णय और आदेश [1] से उत्पन्न होती हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी".) की धारा 302 से आई. पी. सी. की धारा 304-भाग 2 में दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय को परिवर्तित किया गया है। इन अपीलों को सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

2. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि होलिका दहन की पूर्व संध्या पर यानि की 07.03.2012 को, कृष्ण (ए-1) ने सुभाष (मृतक) के साथ दुर्व्यवहार किया।अगले दिन, कृष्ण (ए 6) के बेटे ब्रह्मजीत ने सुबह लगभग 10.00/11.00 सुभाष को डंडा मारा। इसके कारण, दोपहर के लगभग 03.00 बजे, जब पवन, उग्रसेन और सुभाष (मृतक) अपने घर के सामने बैठे थे, तो ब्रह्मजीत उनके घर के पास आया और उन्हें गाली देने लगा, जिससे स्थिति बिगड़ गई।इसके बाद सभी आरोपी कृष्ण (ए 2) का बेटा राजू, कृष्ण, परवीन (ए 3), अमित (ए 4) का बेटा सुंदर, राजपाल (ए 8) का बेटा सुंदर, नर सिंह (ए 7), संदीप (ए 5) और अन्य हथियार लेकर मौके पर पहुंचे।राजू ने सीता राम (पीडब्लू1) के दाहिने कंधे पर प्रहार किया।कृष्ण ने सीता राम की पीठ पर लोहे की नली से प्रहार किया और ब्रह्मजीत ने सीता राम के सिर के दाहिने हिस्से पर फरसा का प्रहार किया।सुंदर के पास एक रॉड थी; नर सिंह और संदीप अपने साथ फरसा ले जा रहे थे।उन्होंने पवन, उग्रसेन और सुभाष को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

1 दिनांकित 27.08.2019 और 03.09.2019

2 आपराधिक अपील सं.249 डी.बी ऑफ 2016 में

3. 09.03.2012 को सूचना मिलने पर, पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 147,148,149 और 323 के तहत मामला दर्ज किया। सुभाष, जो कई चोटों के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया; बाद में, उनकी सर्जरी भी की गई। हालाँकि, वह बच नहीं पाए और 12.3.2012 पर उनका निधन हो गया।इसके बाद, 13.3.2012 को प्राथमिकी में आई.पी.सी की धारा 302 जोड़ी गई।पोस्टमॉर्टम किया गया, और डॉक्टर (पीडब्लू 5-डॉ. कुणाल खन्ना) ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज किया कि मृत्यु मृतक के सिर पर लगी चोटों और उसकी परिचर जटिलताओं के कारण हुई थी।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।बाद में, उनके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर हथियार बरामद किए गए। पीडब्लू 1-सीता राम के बयान पर, अभियोजन पक्ष ने एक अतिरिक्त आरोपी, सुंदर को बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "सी.आर.पी.सी") की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया।

4. सभी आठ अभियुक्त व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा 148,323 और 302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने बाईस गवाहों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।पीडब्लू-3 -डॉ. संत लाल बेनीवाल ने सीता राम (पीडब्लू1), उग्रसेन (पीडब्लू2) और पवन की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं के शरीर पर विभिन्न चोटों को दर्ज किया और कहा कि चोटों की संभावित अवधि छह घंटे के भीतर कुंद हथियार से थी। पीडब्लू8-डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि सुभाष (मृतक) को केवल एक चोट लगी थी।पीडब्लू4-धर्मेंद्र सिंह ने नक्शा तैयार किया।बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की।डी. डब्ल्यू.1-बिक्रम सिंह ने अपदस्थ किया कि वह पेश करने के लिए अधिकृत था, और तदनुसार एक कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति रजिस्टर लाया जिसमें कहा गया था कि 08.03.2012 को (घटना के दिन), एक आरोपी, जो कि, परवीन परमार ने सुबह 07.00 बजे से शाम के 07.00 बजे तक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया था। डी. डब्ल्यू. 2-डॉ. नरेश कुमार, जिन्होंने आरोपी कृष्ण और ब्रह्मजीत की कानूनी रूप से जांच की थी और कृष्ण की दाहिनी क्लैविकल हड्डी का फ्रैक्चर और ब्रह्मजीत की नाक की हड्डी का फ्रैक्चर दर्ज किया था, ने भी बचाव पक्ष के पक्ष में गवाही दी।

5. निचली अदालत ने कहा कि हथियारों से लैस सभी आरोपी एक साथ मौके पर पहुंचे और मृतक सहित पीड़ितों पर उनके हमले ने घातक चोटों को पहुँचाने के लिए एक गैरकानूनी सभा के इरादे को प्रदर्शित किया।मृतक पर पाई गई चोटों की प्रकृति ने संकेत दिया कि सभा का सामान्य इरादा मृत्यु का कारण बना, जो वास्तव में हुआ था।निचली अदालत ने माना कि अभियुक्तों पर लगी चोटों की व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता उन्हें हमले और सुभाष की मौत के कारण की उनकी भूमिका से मुक्त नहीं करती है, क्योंकि सबूत विश्वसनीय थे।दो गवाहों के साक्ष्य ने पुलिस के साथ-साथ अदालत में भी अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का लगातार समर्थन किया।उनकी गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई थी।

निचली अदालत [3] ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 सह पठित धारा 149 के तहत आजीवन कारावास और आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई; आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 323 के तहत अपराध के लिए छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

6. अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने विवादित निर्णय द्वारा उनकी याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उनकी दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 सह पठित धारा 149 से बदलकर 304 भाग II सह पठित धारा 149 आई. पी. सी. में परिवर्तित कर दिया। हालाँकि, इसने आई. पी. सी. की धारा 148 और धारा 323 के साथ धारा 149 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने कहा कि कृष्ण और भारमजीत द्वारा प्राप्त चोटों के बारे में स्पष्टीकरण की कमी ने अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर कर दिया और पीडब्लू.8-डॉ. प्रदीप कुमार के अनुसार, मृतक सुभाष को केवल एक चोट लगी थी।अंत में, उच्च न्यायालय ने माना कि मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है, क्योंकि पक्षों के बीच गुस्सा बढ़ रहा था, और जब शिकायतकर्ता पक्ष कृष्ण के घर के सामने पहुंचा तो अचानक लड़ाई हो गई, जिसका अर्थ था कि आरोपी ने पूर्व-नियोजित तरीके से काम नहीं किया। पीड़ित, सूचना देने वाले उग्रसेन ने दोषसिद्धि के रूपांतरण और सजा में कमी के खिलाफ इस अदालत में अपील की।

7. सुनवाई के दौरान, इस अदालत ने संकेत दिया कि ये अपीलें एक ही अपराध करने के लिए अलग-अलग अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दी गई सजा की उपयुक्तता तक सीमित होंगी।दोषियों द्वारा गुजारी गई विभिन्न अवधियाँ इस प्रकार हैं:कृष्ण को छूट के साथ 9 साल, 5 महीने और 4 दिन का कारावास; राजू को 3 साल, 1 महीने और 1 दिन का कारावास; परवीन को 1 साल, 11 महीने और 27 दिन का कारावास; सुंदर पुत्र अमित लाल को 2 साल और 5 दिन का कारावास; संदीप को 1 साल, 11 महीने और 12 दिन का कारावास; ब्रह्मजीत को 08 साल, 11 महीने और 19 दिन का कारावास (छूट सहित); नर सिंह को 1 साल और 4 महीने का कारावास और सुंदर पुत्र राजपाल को 11 महीने और 16 दिन का कारावास हुआ था।

8. अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि चोटें अचानक लड़ाई के कारण लगी थीं। अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिन अभियुक्तों को समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया था, वे जानबूझकर सूचना देने वाले/पीड़ितों के घर के पास घातक चोटों का कारण बने थे-वास्तव में, सूचना देने वाले पक्षों में से एक की परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई।स्थापित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सभा का उद्देश्य इस तरह के बल का उपयोग करना था, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई।इसलिए, वर्तमान मामले में सजा उचित और उपयुक्त होनी चाहिए थी, और आक्षेपित निर्णय ने सजा के मानक को अपनाने में गंभीर रूप से गलती की, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से अलग और

3.सत्र परीक्षण सं.160 ऑफ 30.07.2012, 275 ऑफ 04.12.2012, 114 ऑफ 15.04.2013 में निर्णय दिनांकित 11.02.2016 और आदेश दिनांकित 17.02.2016।

असमान परिणाम सामने आए।मुकदमे के एक छोर पर, अभियुक्तों में से एक (सुंदर पुत्र राजपाल) को 11 महीने से थोड़ा अधिक समय तक कारावास का सामना करना पड़ा, जबकि कृष्ण को 9 साल, 5 महीने और 4 दिन का कारावास भुगतना पड़ा था।अपीलकर्ता मुखबिरों ने आग्रह किया कि इस अदालत को कुछ हद तक समान सजा मानक अपनाना चाहिए जब प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका व्यावहारिक रूप से अप्रभेद्य थी।

9. अभियुक्त की ओर से यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में इस न्यायालय द्वारा बताए गए हितकारी सिद्धांतों का पालन किया था, जिसमें अभियुक्त की सापेक्ष आयु, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, हिरासत में बिताए गए समय की अवधि, साथ ही साथ अपराध करने के बाद से गुजरे समय की अवधि, सभी पर विचार किया गया था।

10. इस अदालत ने बार-बार कहा है कि आनुपातिकता के सिद्धांत को सजा देने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना चाहिए। *अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैयद बनाम गुजरात राज्य*,[4] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सजा को "*अपराधी को कानून को तोड़ने के लिए घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना चाहिए*", *और "उचित सजा*" देने का प्रयास किया जाना चाहिए।" "अदालत ने यह भी माना कि "*केवल समय बीतने के कारण*" "मामूली सजा" देना प्रतिकूल होगा। इसी तरह, जमील बनाम यू. पी. राज्य[5], में यह वकालत करते हुए कि सजा देना तथ्य पर निर्भर अभ्यास होना चाहिए, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि "कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या प्रतिरोध को अपनाना चाहिए। कुशल मॉड्यूलेशन द्वारा, सजा देने की प्रक्रिया जहाँ होनी चाहिए वहाँ कठोर होनी चाहिए, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ दया के साथ संयमित होना चाहिए।प्रत्येक मामले में तथ्य और दी गई परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी और किया गया था, अपराध करने का उद्देश्य, अभियुक्त का आचरण, उपयोग किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।"

11. फिर से, गुरु बासवराज बनाम कर्नाटक राज्य[6], में अदालत ने जोर देकर कहा कि "यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि अपराध करने और सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव के संबंध में उचित सजा दी जाए" और उस सजा में "पर्याप्त सजा" शामिल है।

---

4 2009 [8] एससीआर 719

5 2009 [15] एससीआर 712

6 2012 [8] एससीआर 189

बी.जी गोस्वामी बनाम दिल्ली प्रशासन[7] , अदालत ने सजा के मुद्दे पर विचार किया और कहा कि सजा संभावित अपराधियों को रोकने के साथ-साथ दोषी पक्ष को अपराध दोहराने से रोकने के लिए बनाई गई है; यह अपराधी को सुधारने और पूरे समाज की भलाई के लिए उसे कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए भी बनाई गई है।सजा के सुधारात्मक, निवारक और दंडात्मक पहलू इस प्रकार उचित सजा देने के प्रश्न का निर्धारण करते समय न्यायिक सोच में अपनी उचित भूमिका निभाते हैं।

12. श्याम सुंदर बनाम पूरन और अन्य[8] में, अभियुक्त-अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलीय अदालत ने सजा को घटाकर छह महीने के कारावास की अवधि में बदल दिया।हालांकि, इसने जुर्माने को बढ़ा दिया।इस अदालत ने फैसला सुनाया कि दी गई सजा अपर्याप्त थी।आगे बढ़ते हुए, इसने राय दी किः-"..... किसी विशेष अपराध के लिए सजा तय करने में अदालत को अपराध की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार-विमर्श की डिग्री को ध्यान में रखना चाहिए। सजा का पैमाना अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा इतनी घोर और पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि इसमें न्याय की विफलता शामिल है।हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सजा को बढ़ाया जाना चाहिए.....।"इस अदालत ने सजा को बढ़ाकर पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा कर दी। इस अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि सजा तथ्यों पर निर्भर करती है, और पर्याप्तता "अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से यह किया जाता है, दिखाई गई प्रवृत्ति और प्रतिबिंबित क्रूरता" जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।[रावदा शशिकल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[9]] अन्य निर्णय, जैसे एम.पी राज्य बनाम बबलू[10] ; राज कुमार[11] और पंजाब राज्य बनाम सौरभ बख्शी[12] ने भी उचित, "पर्याप्त" या "आनुपातिक" दंड लगाने के महत्ता और महत्व पर जोर दिया है।

---

7 1974 (1) एससीआर 222

8 1990 पूरक [1] एससीआर 662

9 2017 [2] एससीआर 379

10 2014 [9] एससीआर 467

11 2013 (5) एससीआर 979

12 2015 (3) एससीआर 590

13. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने दोषीगण-जो है:- कृष्ण (61 वर्ष); राजू (40 वर्ष); परवीन (32 वर्ष); सुंदर (39 वर्ष); संदीप (25 वर्ष); नर सिंह (41 वर्ष) और सुंदर पुत्र राजपाल (36 वर्ष) की संबंधित आयु का उल्लेख किया।अदालत ने नोट किया कि ब्रह्मजीत ने सेना में सेवा की थी।इनके अलावा, अदालत ने सापेक्ष पारिवारिक परिस्थितियों पर ध्यान दियाः प्रत्येक आरोपी के बच्चों की संख्या का।इसके बाद इसने एक समान नियम, वह है, अभियुक्त द्वारा दी गई सजा की अवधि को उचित सजा के रूप में अपनाया।

14. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत समवर्ती रूप से दोषी पाया गया था; वे विभिन्न प्रकार के उपकरणों और हथियारों से लैस थे, जो घातक चोट पहुंचाने में सक्षम थे।सुभाष की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर कम से कम छह गंभीर चोटों का पता चला, जिसमें विभिन्न स्थानों पर फ्रैक्चर और रक्तस्राव शामिल हैं।पवन, उग्रसेन और सीता राम, शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य लोगों को भी चोटें आईं।हालांकि उच्च न्यायालय की राय थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों को लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, लेकिन उनका स्वभाव गंभीर नहीं लगता है।किसी भी तरह से, अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 304 II के सह पठित धारा 149 के तहत सजा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया।

15. इस मामले में सजा, इसे हल्के से कहने के लिए, अकथनीय है (यदि बिल्कुल विचित्र नहीं है)।एक ओर कृष्ण को 9 साल 4 महीने की सजा सुनाई गई-दूसरी ओर सुंदर पुत्र राजपाल को केवल 11 महीने की सजा सुनाई गई।इस व्यापक असमानता के लिए उच्च न्यायालय के तर्क से कोई तर्क नहीं मिलता है।ऐसा नहीं है कि अदालत ने अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान दिया (साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं था)। यदि यह माना जाता है कि अभियुक्त की आयु ने एक भूमिका निभाई है, तो कृष्ण, 61 वर्ष की आयु में-जिन्होंने 9 वर्ष की सेवा की थी और ब्रह्मजीत, जिन्होंने सेना में सेवा की थी, और जिन्हें 8 वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था, उन्हें सबसे कठोर सजा मिली।पैमाने के दूसरे छोर पर, 3 साल से 11 महीने के बीच सेवा करने वाले युवा व्यक्तियों को अपेक्षाकृत सही सलामत छोड़ दिया गया था।

16. इस अदालत की राय में, अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं करने में आक्षेपित निर्णय त्रुटि में पड़ गया।आई. पी. सी. की धारा 149 के सह पठित धारा 304 भाग 2 के तहत सभी अभियुक्तों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने और उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई अलग-अलग भूमिकाओं के रूप में कोई विशिष्ट विशेषता नहीं पाए जाने के बाद, "सजा सुनाई गई" मानदंड को लागू करना एक विचलन के बराबर है, और सजा उस कारण से त्रुटिपूर्ण है।इसलिए, इस अदालत का विचार है कि परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए (जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आरोपी पिछले चार वर्षों से फरार हैं), उपयुक्त सजा पांच साल के कठोर कारावास की होगी।हालाँकि, साथ ही, अदालत इस तथ्य से अवगत है कि कृष्ण और ब्रह्मजीत ने उस अवधि से अधिक सेवा की।इसलिए, जहां तक उनका संबंध है, आक्षेपित निर्णय को अबाधित छोड़ दिया जाता है।नतीजतन, राजू, परवीन, सुंदर पुत्र अमित लाल, संदीप, नर सिंह और सुंदर पुत्र राजपाल की सजा को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता

है; उन्हें एतद्द्वारा पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।वे आत्मसमर्पण करेंगे और आज से छह सप्ताह के भीतर अपनी शेष सजा काट लेंगे।

17. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।कोई कॉस्ट नहीं।

..... जे.

[एस. रवींद्र भट्ट]

..... जे.

[दीपांकर दत्ता]

नई दिल्ली

3 जुलाई, 2023।

अस्वीकरण:– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।